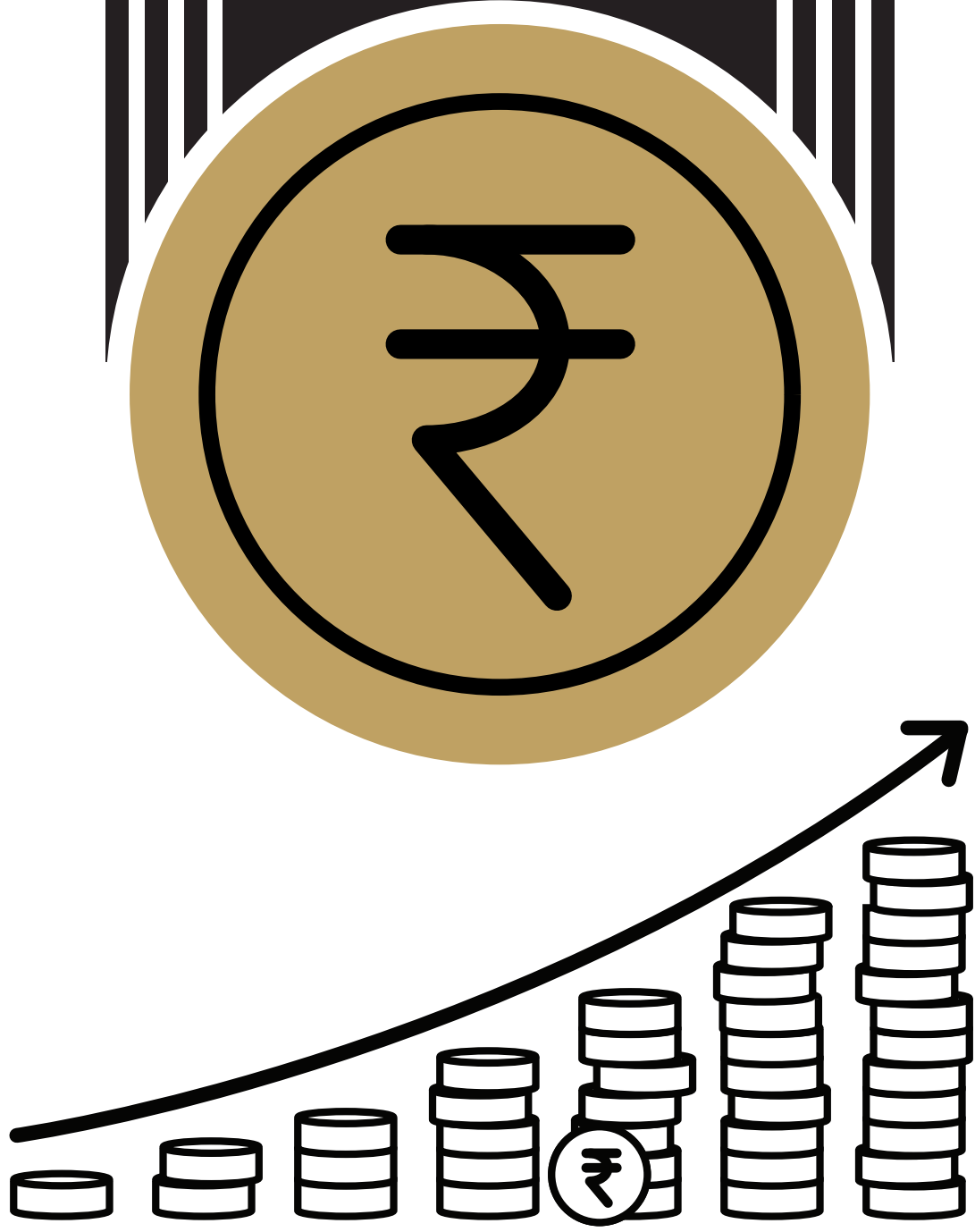
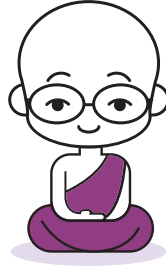




UPSC PATHSHALA

अर्थशास्त्र



## प्रस्तावना

भारतीय अर्थव्यवस्था सिविल सेवा परीक्षा के तीनों चरणों में सबसे महत्वपूर्ण, आवश्यक और मुख्य विषयों में से एक है। यह विशेष विषय आपको भारतीय बैंकिंग प्रणाली की प्रकृति, भारत में विभिन्न अर्थव्यवस्था से संबंधित बाजारों, सामान्य आर्थिक विकास और बहुत कुछ को समझने के लिए आवश्यक ज्ञान प्रदान करती है।

विषय की तकनीकी प्रकृति और उसमें विभिन्न अवधारणाओं की उपस्थिति के कारण अर्थव्यवस्था को समझना जटिल हो जाता है। चीजों को सरल बनाने के लिए, हमने अर्थव्यवस्था के दायरे और वेटेज का विश्लेषण किया है और यूपीएससी उम्मीदवारों को अधिकतम आउटपुट प्राप्त करने के लिए पुस्तक तैयार की है।

इस पुस्तक के प्रत्येक अध्याय को सरल भाषा का उपयोग करते हुए विस्तृत रूप से लिखा गया है जिससे एक उम्मीदवार के लिए विषय के सार को समझना आसान हो जाएगा और यह अपने पाठकों को वैचारिक स्पष्टता प्रदान करता है और परीक्षा में विभिन्न प्रकार और प्रश्नों की प्रकृति के उत्तर देने में सभी छात्रों की मदद करता है।

# 01

## भारत में बैंकिंग

---

### परिचय

बैंक एक अर्थव्यवस्था के शरीर में एक महत्वपूर्ण अंग की भूमिका निभाता है। यह प्रभावी रूप से जमा राशि जुटाता है और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऋण के निपटान के लिए जिम्मेदार है। बैंक एक वित्तीय संस्थान है जिसे उपभोक्ताओं के पैसे को जमा राशि के रूप में जमा करने और व्यक्तियों और व्यवसायों को पैसा उधार देने के लिए लाइसेंस दिया जाता है, भुगतान का संवितरण और वित्तीय परिसंपत्तियों और प्रतिभूतियों में निवेश आदि करते हैं। बैंक, शुल्क और भुगतान की गई ब्याज दरों के अंतर से मुनाफ़ा कमाता है।

बैंक उन लोगों के बीच एक माध्यम के रूप में कार्य करते हैं जिनके पास धन का अधिशेष है और जिन्हें इसकी आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, बैंक अंतिम उधारकर्ता के संभावित चूक से उत्पन्न होने वाले जोखिम उठाता है। इस प्रकार यह लोगों से जमा स्वीकार करता है और ऋण बनाकर ऋणों को आगे बढ़ाता है।

---



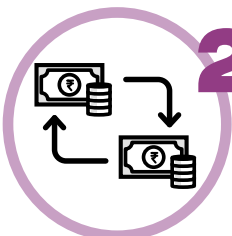
## बैंकिंग के कार्य क्या हैं?

### What are the functions of Banking?

बैंक के निम्नलिखित कार्य बैंक की आवश्यकता और इसके महत्व को समझाते हैं:



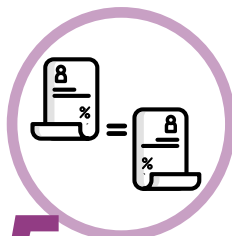
1 ग्राहकों की बचत को सुरक्षा प्रदान करना।



2 पैसे और जमा धन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए।

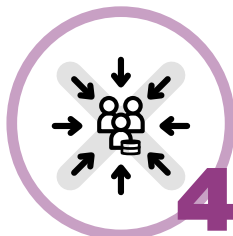


3 वित्तीय प्रणाली के काम में जनता के विश्वास को प्रोत्साहित करने के लिए, बचत को तेजी से और प्रभावी ढंग से बढ़ाने के लिए।



5

सभी प्रकार के ग्राहकों के लिए समान मानदंड और शर्तें (यानी ब्याज की दर, उधार देने की अवधि आदि) निर्धारित करना।



4

कुछ व्यक्तियों और संस्थानों के हाथों में वित्तीय शक्तियों के केन्द्रीकरण से बचने के लिए।

## केंद्रीय बैंक - आरबीआई (Central Bank - RBI)

आरबीआई देश के बैंकिंग और वित्तीय ढांचे में एक शीर्ष संस्था है जो अर्थव्यवस्था के बैंकिंग और वित्तीय ढांचे को व्यवस्थित करने, चलाने, पर्यवेक्षण, विनियमन और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत के केंद्रीय बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक के रूप में जाना जाता है। सैमुएलसन के अनुसार, एक केंद्रीय बैंक बैंकरों के लिए एक बैंक है। यह अर्थव्यवस्था का मौद्रिक प्राधिकरण है जो विकास को बढ़ावा देने और संतुलन बनाने के साथ-साथ मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए धन के प्रबंधन का काम करता है।

## आरबीआई की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? (What is the Historical Background of RBI?)

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 ने रिज़र्व बैंक को केंद्र सरकार के लिए बैंकर के रूप में स्थापित किया और 1 अप्रैल, 1935 को संचालन की शुरुआत में समापन कार्यों की एक श्रृंखला निर्धारित की।

1934

1926

1949

1926 में, भारतीय मुद्रा और वित्त पर रॉयल कमीशन जिसे हिल्टन-यंग कमीशन के नाम से भी जाना जाता है- ने एक केंद्रीय बैंक बनाने की सिफारिश की।

इनके दो विचार थे, सबसे पहले सरकार से मुद्रा और ऋण के नियंत्रण को अलग करना। दूसरा, पूरे देश में बैंकिंग सुविधाओं को बढ़ाना।

1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया।

### क्षेत्र

दिल्ली

उत्तरी

कोलकाता

पूर्वी

चेन्नई

दक्षिणी

मुंबई

पश्चिमी

दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई में चार क्षेत्रों में इसके चार क्षेत्र हैं: क्रमशः उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र। आरबीआई के 19 कार्यालय हैं, जो राज्य की राजधानियों और भारत के कुछ प्रमुख शहरों में स्थित हैं। इसके अलावा, आरबीआई के 9 उप-कार्यालय हैं।

## आरबीआई के कार्य क्या हैं?

(What are the functions of RBI?)

### निर्गमन करने का बैंक (Bank of Issue):

मुद्रा विभाग और सिक्कों को जारी करने का एकमात्र अधिकार निर्गम विभाग के माध्यम से है, जो केवल नोटों और सिक्कों के मुद्दे के लिए जिम्मेदार है। यह मुद्रा में एकरूपता प्रदान करता है और देश के प्रत्येक नागरिक द्वारा पहचान की गई आवश्यक प्रतिष्ठा को जोड़ता है।

### बैंकों और सरकार के लिए एक बैंकर (Banker to Banks and Government):

बैंकर बैंक के रूप में, आरबीआई वाणिज्यिक और अन्य बैंकों के नकदी भंडार के

संरक्षक के रूप में कार्य करता है। सरकार को भी निजी क्षेत्र की तरह बैंक की सेवाओं की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य खातों को बनाए रखना, एक वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य करना, सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करने के साथ-साथ विदेशी मुद्रा भंडार के संरक्षक का कार्य भी करता है। चूंकि आरबीआई शीर्ष बैंक है, इसलिए वाणिज्यिक बैंकों के प्रति इसके कुछ अधिकार और जिम्मेदारियां भी हैं।

- वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक के पास अपनी जमा राशि का एक हिस्सा रखने के लिए वैधानिक दायित्व के तहत जिम्मेदार हैं।
- केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को मुख्य रूप से अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। यह उन्हें मार्गदर्शन और दिशा प्रदान करता है और उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करता है।
- वाणिज्यिक बैंकों को केंद्रीय बैंक के इन निर्देशों और मार्गदर्शन के अनुसार अपनी नीति को आकार देने की आवश्यकता होती है।
- बैंकर और सरकार के वित्तीय सलाहकार के रूप में, केंद्रीय बैंक को सरकार से नकद, चेक, ड्राफ्ट आदि की जमा राशि प्राप्त होती है।
- यह सरकार को वेतन और मजदूरी और अन्य नकद संवितरण का भुगतान करने के लिए नकद राशि प्रदान करता है। यह सरकार की ओर से भुगतान करता है।
- यह सरकार को कम अवधि का ऋण देता है। यह सरकार की ओर से विदेशी मुद्राएं खरीदता और बेचता है।

### अंतिम उपाय का ऋणदाता(Lender of Last Resort):

आर बी आई वाणिज्यिक बैंकों की मदद करता है जब उन्होंने अपने संसाधनों को समाप्त कर दिया है और वित्तीय राशि की जरूरत है। अंतिम उपाय के ऋणदाता के रूप में, केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी उचित वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

### ऋण नियंत्रक(Controller of Credit):

आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों द्वारा धन निर्माण को नियंत्रित करता है जिसे सेंट्रल बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। वर्तमान में, साख मुद्रा या बैंक मुद्रा पैसे का प्रमुख रूप है और अनिवार्य रूप से धन की आपूर्ति को विनियमित करने की आवश्यकता है ताकि अर्थव्यवस्था के सुचारु कामकाज को सुनिश्चित किया जा सके। इसके लिए, केंद्रीय बैंक धन नियंत्रण की मात्रात्मक और गुणात्मक तरीके अपनाता है। मात्रात्मक तरीकों का उद्देश्य धन की लागत और उपलब्धता को नियंत्रित करना है, जबकि गुणात्मक विधि धन के उपयोग और दिशा को प्रभावित करती है।

### केंद्रीय निकासी और निपटान बैंक (Bank of Central Clearance and Settlement):

यह वाणिज्यिक बैंकों के आपसी दावों को निपटाने के लिए समाशोधन गृह के रूप में कार्य करता है। वाणिज्यिक बैंक अपने परस्पर दावों को निपटाने के लिए समाशोधन गृह में मिलते हैं। प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों द्वारा जमा किए गए चेक प्राप्त करता है, जिन्हें वो अन्य बैंकों से मांग/दावा कर सकते हैं। चूंकि केंद्रीय बैंक इन बैंकों का भंडार रखता है, इसलिए इसे अपने खातों में सरल स्थानांतरण प्रविष्टियों के माध्यम से निपटाया जा सकता है।

### सेंट्रल बैंक वाणिज्यिक बैंकों से कैसे अलग है? (How is the Central Bank different from Commercial Banks?)

#### लाभ के आधार पर (On the basis of Profit):

एक केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंक की तरह लाभ कमाने का लक्ष्य नहीं रखता है और इसलिए वह लाभ कमाने वाली संस्था नहीं है। यह जनहित में कार्य करता है ताकि देश की बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली को नियमित और विनियमित किया जा सके।

#### किए गए कार्यों के आधार पर (On the basis of functions performed):

एक केंद्रीय बैंक साधारण वाणिज्यिक बैंकिंग कार्य नहीं करता है जैसे कि देश की आम जनता से जमा स्वीकार करना।

#### स्वामित्व (Ownership):

एक केंद्रीय बैंक सरकार का एक अंग है और इसलिए, इसका स्वामित्व सरकार के पास है और सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रबंधित किया जाता है। लेकिन एक वाणिज्यिक बैंक आमतौर पर दोनों निजी व्यक्तियों द्वारा शेयरधारकों और सरकार द्वारा स्वामित्व में होता है।

#### मुद्रा जारी करने वाला (Issuer of Currency):

एक केंद्रीय बैंक में नोट जारी करने का एकाधिकार होता है, लेकिन वाणिज्यिक बैंक नोट जारी नहीं कर सकते।

## विकास कार्य(Development Function):

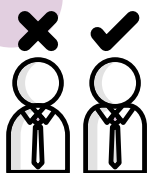
केंद्रीय बैंक का व्यवसाय वाणिज्यिक बैंकों को इस तरह से नियंत्रित करना है जो राज्य की सामान्य मौद्रिक नीति को बढ़ावा देता है। यह वाणिज्यिक बैंकों से बेहतर है क्योंकि यह बैंकिंग प्रणाली के विस्तार, नए वित्तीय संस्थानों की स्थापना, धन और पूँजी बाजार के विकास के साथ-साथ निवेश को बढ़ावा देने के लिए भी जिम्मेदार है।



लाइसेंस देने की शक्ति।



बैंकों का निरीक्षण और पर्यवेक्षण करने की शक्ति।



बैंकिंग बोर्ड कर्मियों को नियुक्त करने या हटाने की शक्ति।



क्रेडिट जानकारी एकत्र करने और प्रस्तुत करने की शक्ति



बैंकों के व्यवसाय को विनियमित करने की शक्ति।



दिशा देने की शक्ति।



दंड लगाने की शक्ति।





# बैंकिंग के साथ जुड़ी शब्दावली

(Terms Associated with Banking)

## मौद्रिक नीति (Monetary Policy)

- मौद्रिक नीति देश के मौद्रिक प्राधिकरण(Monetary Authority) द्वारा शुरू की गई नीति है। इसके दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और दूसरा, मूल्य अस्थिरता को कायम रखना। ये दोनों कार्य मुद्रा स्थिति को एक सीमा या दायरे में सीमित रख कर किये जाते हैं।
- मौद्रिक नीति को लागू करने के लिए आरबीआई मुख्य संस्था है। आरबीआई ने आर्थिक विकास के पर्याप्त वित्तपोषण और उचित मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के साथ-साथ अपनी मौद्रिक नीति को भी परिभाषित किया है।

## बैंक दर (Bank Rate )

- वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। दूसरे शब्दों में, यह वह दर है जिस पर आरबीआई विनिमय के बिल का पुनः निर्धारण करता है।
- यह इस प्रकार मौद्रिक नीति की दिशा में अर्थव्यवस्था के लिए एक संकेत के रूप में कार्य करता है। आरबीआई विनिमय दर और घरेलू मुद्रास्फीति में उतार-चढ़ाव को विनियमित करने के लिए बैंक दर में परिवर्तन करता है।
- प्रत्येक बैंक आधार दर तय करने के लिए स्वतंत्र है जिसके नीचे वह उधारकर्ताओं को उधार नहीं देगा। बैंकों को तल चिन्ह(Benchmark) घोषित करना चाहिए जिसके आधार पर ऐसी आधार दरें तय की जाती हैं। एक बैंक में एक ही तल चिन्ह हो सकता है।
- वर्तमान में यह 5.4% है।

## नकद आरक्षित अनुपात (Cash Reserve Ratio (Crr))

- प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक को आरबीआई (या तो नकद या खाता शेष के रूप में) के साथ अपनी मांग और समय देनदारियों (जमा) का एक निश्चित प्रतिशत रखने की आवश्यकता होती है।
- आरबीआई इस अनुपात को बदलता है जब वह महसूस करता है कि धन की आपूर्ति को बढ़ाने या घटाने की आवश्यकता है।
- आरबीआई को सीआरआर 3 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक की दर से तय करने का अधिकार है।
- आरबीआई इस पद्धति (सीआरआर दर में वृद्धि) का उपयोग करता है, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को अनुबंधित करने के लिए धन निकाला जा सके।
- वर्तमान में सीआरआर 4% है।

## वैधानिक तरलता अनुपात (Statutory Liquidity Ratio (Slr))

- वाणिज्यिक बैंकों को नकदी, सोना, या अनुमोदित प्रतिभूतियों के आकार में तरल संपत्ति के रूप में अपनी शुद्ध मांग और समय देनदारियों (Net Demand And Time Liabilities-Ndtl) का एक निश्चित प्रतिशत (सीआरआर के अलावा) रखने की आवश्यकता होती है।
- जैसा कि अधिकांश एसएलआर धन राजकोष के बिलों में रखा जाता है, सरकार ने अतीत में, एसएलआर का इस्तेमाल कम लागत वाले संसाधनों को जुटाने के लिए किया था। एसएलआर के इस दुरुपयोग से ब्याज दर और ऋण आपूर्ति में विकृति आती है।
- इसे दूर करने के लिए, नरसिम्हन समिति ने सिफारिश की कि एसएलआर को 25 प्रतिशत तक लाया जाए, जो कि 1993-94 के बाद की वर्तमान दर है।
- वर्तमान में एसएलआर 21.50% है।

## खुला बाजार संचालन (Open Market Operation)

- यह आरबीआई को मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करने के लिए योग्य प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने के लिए संदर्भित करता है।
- परंपरागत रूप से, आरबीआई इस पद्धति का सहारा नहीं ले रहा था। हालांकि, 1991 के बाद से विदेशी कोष की बड़ी आमद के बाद, आरबीआई ने अतिरिक्त तरलता से बचने के लिए, इस कदम का सहारा लिया।

## तरलता समायोजन की सुविधा (Liquidity Adjustment Facility (Laf))

- तरल समायोजन सुविधा एक मौद्रिक नीति उपकरण है जो बैंकों को पुनर्खरीद समझौतों के माध्यम से धन उधार लेने की अनुमति देता है। एलएएफ का उपयोग बैंकों को दिन-प्रतिदिन की तरलता में असंतुलन को समायोजित करने के लिए किया जाता है। एलएएफ में रेपो और रिवर्स रेपो संचालन होते हैं।

## रेपो दर (Repo Rate)

- पुनर्खरीद विकल्प (Repo) वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। दूसरे शब्दों में, यह वह दर है जिस पर हमारे बैंक आरबीआई से रुपये उधार लेते हैं।
- जब बैंकों के पास धन की कोई कमी होती है तो वे इसे आरबीआई से उधार ले सकते हैं। रेपो रेट में कमी से बैंकों को सस्ती दर पर पैसा मिल सकेगा।
- जब रेपो रेट बढ़ता है, तो आरबीआई से उधार लेना और महंगा हो जाता है।
- वर्तमान में रेपो दर 5.15% है।

## रिवर्स रेपो दर (Reverse Repo Rate)

- जिस दर पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) बैंकों से पैसा उधार लेता है और इसलिए रेपो दर के बिल्कुल विपरीत होता है।
- आरबीआई इस उपकरण का उपयोग तब करता है जब उसे लगता है कि बैंकिंग प्रणाली में बहुत अधिक पैसा तैर रहा है। बैंक हमेशा आरबीआई को पैसे उधार देने में खुश होते हैं क्योंकि उनका पैसा अच्छे हाथों में सुरक्षित होता है अच्छे ब्याज के साथ।
- रिवर्स रेपो दरों में वृद्धि से बैंक अपने आकर्षक ब्याज के कारण आरबीआई को अधिक धनराशि हस्तांतरित कर सकते हैं।
- आरबीआई, सीआरआर और बैंक दर में बदलाव जैसे प्रमुख नीतिगत साधनों का सहारा लिए बिना तरलता की स्थिति को ठीक करने के लिए रेपो मार्ग का समर्थन करता है। हालांकि, बाजार रेपो दरों में लगातार बदलावों पर प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य हैं और यह वाणिज्यिक बैंकों की जमा और उधार दरों में संबंधित परिवर्तनों में परिलक्षित होगा।
- वर्तमान में, रिवर्स रेपो दर 4.90% है।

## न्यूनतम उधार दर (Prime Lending Rate)

- यह बैंकों द्वारा अपने सबसे अधिक ऋण लेने वाले ग्राहकों (आमतौर पर सबसे प्रमुख और स्थिर व्यावसायिक ग्राहक) के लिए ब्याज दर है।
- प्रमुख बैंकों में यह दर लगभग हमेशा एक जैसी है।
- कुछ बैंक अपने न्यूनतम उधार दर को संदर्भित करने के लिए “संदर्भ दर” या “मूल लेंडिंग दर” नाम का उपयोग करते हैं।

## सीमांत स्थायी सुविधा (Marginal Standing Facility (MsF))

- सरकारी प्रतिभूतियों के विरुद्ध आरबीआई से रातोंरात धनराशि बैंक द्वारा उधार ली जा सकती है।
- बैंकों द्वारा नकदी की गंभीर कमी या तरलता में कमी होने की स्थिति में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए यह एक अल्पकालिक उधार योजना है।
- बैंकों के बाजार में रातोंरात उधार दरों में अस्थिरता को कम करने और वित्तीय प्रणाली में एक सहज मौद्रिक संचरण को सक्षम करने के लिए आरबीआई द्वारा एमएसएफ की शुरुआत की गई है।
- वर्तमान में एमएसएफ की दर 5.65% है।

# भारत में बैंकिंग: बैंकों का वर्गीकरण

## (Banking in India : Classification of banks )

बैंकों को संगठित और असंगठित बैंकिंग में वर्गीकृत किया गया है

| असंगठित बैंकिंग (Un-organized Banking):                                                                                                                                           | संगठित बैंकिंग (Organised Banking):                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| भारतीय बैंकिंग प्रणाली का वह हिस्सा जो हमारे केंद्रीय बैंक (यानी भारतीय रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया) के नियंत्रण में नहीं आता, असंगठित बैंकिंग कहलाता है। उदाहरण के लिए स्वदेशी बैंक। | अनुसूचित बैंक वे हैं जो आरबीआई अधिनियम, 1939 की दूसरी अनुसूची में दर्ज किए जाते हैं। अनुसूचित बैंक वे बैंक होते हैं जिनकी भुगतान की गई पूंजी होती है और कुल 5 लाख रुपये से कम के सकल मूल्य के भंडार होते हैं और जो आरबीआई के दिशानिर्देशों को पूरा करते हैं। |

संगठित (अनुसूचित) बैंकिंग क्षेत्र को तीन प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

देश का केंद्रीय बैंक  
(आरबीआई)

वाणिज्यिक बैंक

सहकारी बैंक

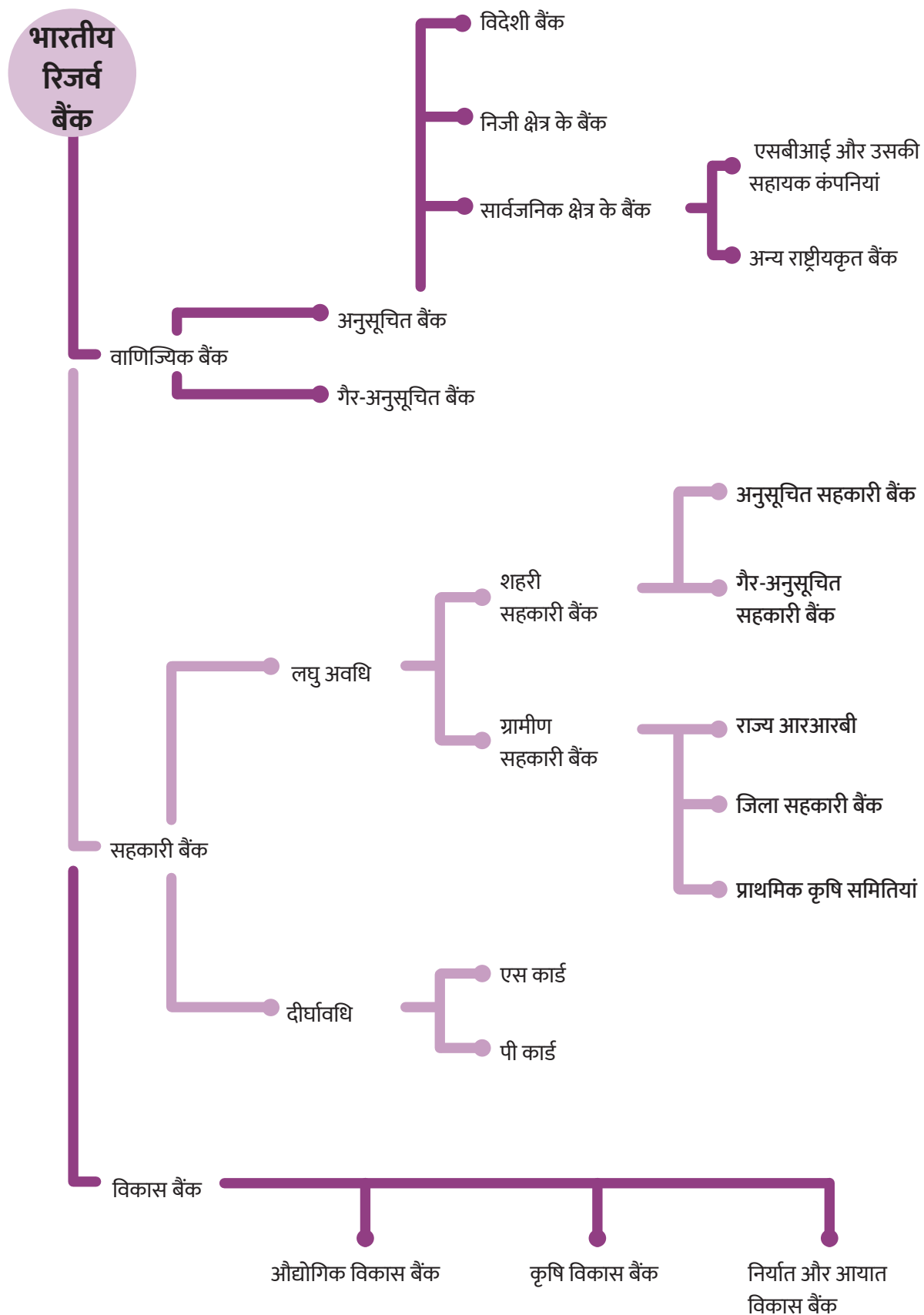
## वाणिज्यिक बैंक (Commercial Banks )

वाणिज्यिक बैंक वित्तीय संस्थान हैं जो धन का सौदा करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ होता है। इससे जुड़े पैसे का एक बड़ा हिस्सा जनता से आता है। यह उधारदाताओं और उधारकर्ताओं के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (Scbs ) निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत हैं:

**राष्ट्रीयकृत बैंक (Nationalised Banks )** - भारतीय स्टेट बैंक और इसके सहयोगी राष्ट्रीयकृत बैंकों जैसे Idbi बैंक, इंडियन बैंक, देना बैंक आदि सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में देश में संचालित आईसीआईसीआई, एक्सिस, एचडीएफसी बैंक आदि जैसे निजी बैंक शामिल हैं।

**विदेशी बैंक (Foreign Banks)** - देश में परिचालन में ड्यूश बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी बैंक, एचएसबीसी और रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड आदि शामिल हैं।

**क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (Regional Rural Banks)** - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1970 के दशक में ग्रामीण क्षेत्रों खासकर छोटे और सीमांत किसानों, खेतिहर मज़दूरों और छोटे उद्यमियों लोगों को जमा और ऋण सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से अस्तित्व में आए। भले ही ये बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के रूप में गिने जाते हैं लेकिन उनका ध्यान और पहुंच आम तौर पर एक जिले या दो तक सीमित है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कुछ उदाहरण असम ग्रामीण विकास बैंक, इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक, बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, आदि हैं। वर्तमान में, भारत में 91 आरआरबी कार्यरत हैं।



## सहकारी बैंक (Cooperative Banks)

यह सहकारी सिद्धांतों के आधार पर स्थापित संस्था है और 'ना लाभ ना हानि आधार' के साथ साधारण बैंकिंग व्यवसाय में काम करती है। ये बैंक सहकारी समितियों द्वारा नियंत्रित, स्वामित्व, प्रबंधित और संचालित हैं और 1912 में सहकारी समितियों अधिनियम के तहत अस्तित्व में आया। ये बैंक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। हालांकि इन बैंकों के वाणिज्यिक बैंकों के समान कार्य हैं, लेकिन अन्य बैंकों की तुलना में उनकी ब्याज दर कम है।

वर्तमान में, देश में 170 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं, जिसमें 91 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), 19 राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय स्टेट बैंक समूह के 8 बैंक और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लिमिटेड (Idbi Ltd) शामिल हैं।

### सहकारी बैंकों के तीन प्रकार क्या हैं? (What Are The Three Types Of Cooperative Banks?)

भारत में तीन प्रकार के सहकारी बैंक हैं, अर्थात्

| प्राथमिक क्रेडिट सोसाइटी                                                                                                                                                                              | केंद्रीय सहकारी बैंक                                                                                                                                                                                                                                                            | राज्य सहकारी बैंक                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Primary Credit Societies): ये एक छोटे से इलाके जैसे छोटे शहर या गाँव में बनाई जाती हैं। इस बैंक का उपयोग करने वाले सदस्य आमतौर पर एक-दूसरे को जानते हैं और धोखाधड़ी करने की संभावना न्यूनतम होती है। | (Central Cooperative Banks): इन बैंकों के अपने सदस्य होते हैं जो एक ही जिले के होते हैं। वे अन्य वाणिज्यिक बैंकों के रूप में कार्य करते हैं और अपने सदस्यों को ऋण प्रदान करते हैं। वे राज्य सहकारी बैंकों और प्राथमिक क्रेडिट सोसायटी के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। | (State Cooperative Banks): इन बैंकों की शाखा देश के सभी राज्यों में उपस्थिति है और पूरे राज्य में उनकी उपस्थिति है। |

## गैर-अनुसूचित बैंक (Non-Scheduled Banks)

ये बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते हैं। इन्हें स्थानीय क्षेत्र बैंक के रूप में भी जाना जाता है। गैर-अनुसूचित बैंक भी वैधानिक नकदी आरक्षित आवश्यकता के अधीन हैं। लेकिन उन्हें आरबीआई के पास रखने की आवश्यकता नहीं है; वे अपने साथ इन पूंजी को रख सकते हैं।

वे सामान्य बैंकिंग उद्देश्यों के लिए आरबीआई से उधार लेने के हकदार नहीं हैं, हालांकि वे असामान्य परिस्थितियों में सहयोग के लिए आरबीआई से संपर्क कर सकते हैं।

### भारत में 5 गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक क्या हैं? (What Are The 5 Non-Scheduled Urban Cooperative Banks In India?)

अखंड आनंद  
को-ऑपरेटिव बैंक  
लिमिटेड।

अलवी को-  
ऑपरेटिव बैंक  
लिमिटेड।

अमरनाथ को-  
ऑपरेटिव बैंक  
लिमिटेड।

आमोद नागरिक  
सहकारी बैंक  
लिमिटेड।

अमरेली नागरीक  
सहकारी बैंक  
लिमिटेड।

ऊपर दिए गए बैंकों के अलावा, निम्नलिखित बैंक भी, आरबीआई के अनुसार बैंकिंग की गैर-अनुसूचित सूची में आते हैं।

तटीय स्थानीय  
क्षेत्र बैंक लिमिटेड

कैपिटल  
लोकल एरिया  
बैंक लिमिटेड

कृष्णा भीम समृद्धि  
लोकल एरिया  
बैंक लिमिटेड

सुभद्रा लोकल  
एरिया बैंक  
लिमिटेड

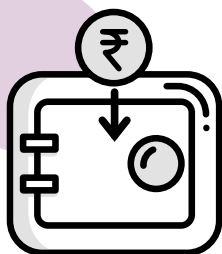
## वाणिज्यिक बैंकों के कार्य क्या हैं?

(What are the functions of Commercial Banks?)

एक वाणिज्यिक बैंक के कार्यों को प्राथमिक और माध्यमिक में विभाजित किया जा सकता है। प्राथमिक कार्य बैंकिंग कार्य होते हैं जबकि माध्यमिक कार्यों को गैर-बैंकिंग कार्यों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हम दोनों प्रकार के कार्यों के बारे में विस्तृत समझ के साथ आगे बढ़ेंगे।

## बैंकिंग कार्य(Banking Functions)

बैंकिंग कार्यों के दायरे में जमा और ऋण को आगे बढ़ाना दो महत्वपूर्ण अंग हैं।



### जमा (Deposits)

**चालू खाता जमा(Current Account Deposits):** चालू खाता जमा को डिमांड डिपॉजिट के रूप में भी जाना जाता है। एक चालू खाता जमा आमतौर पर कारोबारियों द्वारा संचालित किया जाता है। यह न्यूनतम तरलता दबाव के साथ व्यापार लेन देन को संभव बनाता है। चालू खाता जमा पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। बैंक इस सुविधा को प्रदान करने के लिए शुल्क लगा सकते हैं।

**बचत बैंक जमा(Savings Bank Deposits):** ये खाते वेतन भोगी और निम्न आय वाले व्यक्तियों के लिए खोले जाते हैं। इसे थोड़े से पैसे की जमा राशि में खोला जा सकता है। इसमें जरूरत पड़ने पर, बहुत दायित्वों के बिना पैसे वापस लिए जा सकते हैं। यह सावधि जमा की तुलना में बहुत कम ब्याज अर्जित करता है।

**सावधि जमा(Fixed Deposits):** इस खाते में पैसा एक निश्चित अवधि के लिए जमा किया जाता है। समय अवधि लगभग 3 महीने से लेकर 3 साल तक हो सकती है। ये एक बैंक के ग्राहकों द्वारा ब्याज अर्जित करने के लिए जमा राशि हैं। इस तरह की जमा राशि में अन्य प्रकार की जमा राशियों की तुलना में उच्च ब्याज दर होती है। यदि ग्राहक जमा की निर्धारित अवधि समाप्त होने से पहले पैसा निकालता है, तो उसे जुर्माना देना होगा।

**आवर्ती जमा(Recurring Deposits):** इस प्रकार की जमा राशि लोगों में छोटी बचत की आदत विकसित करना है। इसके तहत, जमाकर्ताओं को नियमित रूप से निर्धारित समय में एक निश्चित राशि जमा करनी होती है। जमा राशि, एक तय की गई अवधि के लिए जारी रहती है। उस पर ब्याज दर सावधि जमा के काफी समान रहती है।

### ऋण और अग्रिम(Loans And Advances)

वाणिज्यिक बैंक उद्योगों, व्यक्तियों, व्यवसायों, कृषि आदि को ऋण प्रदान करके अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे निर्यात और आयात व्यापार के लिए ऋण भी प्रदान करते हैं।

**उपयोगिता सेवाएं(Utility Services):** वाणिज्यिक बैंक ग्राहक के लिए उपयोगी विभिन्न सेवाओं का प्रदर्शन करते हैं।

**लॉकर सुविधा(Locker Facility):** बैंक ग्राहकों को अपने कीमती सामान, जैसे कि प्रतिभूतियां, आभूषण, दस्तावेज आदि रखने के लिए लॉकर सुविधा प्रदान करते हैं।

**ड्राफ्ट सुविधाएं(Draft Facility):** बैंक ग्राहकों को ड्राफ्ट जारी करते हैं और उन्हें जगह-जगह से धन हस्तांतरित करने में सक्षम बनाते हैं।

**ऋण पत्र(Letters Of Credit):** बैंक अपने ग्राहकों को ऋण पत्र जारी करते हैं। ये विदेशों में क्रेडिट पर माल खरीदने के लिए व्यापारियों के लिए उपयोगी हैं। यह क्रेडिट बैंक द्वारा एक स्थान पर जारी किया जाता है।

**एजेंसी सेवाएं(Agency Services):** वाणिज्यिक बैंक भी अपने ग्राहकों के पक्ष में / उनकी ओर से कई गतिविधियाँ करते हैं।

**संग्रह(Collections):** वाणिज्यिक बैंक एजेंटों के रूप में अपने ग्राहकों की ओर से वचन पत्र, चेक, बिल, लाभांश, सदस्यता, किराए आदि का संग्रह लेते हैं। बैंक इन सेवाओं को अपने ग्राहकों को प्रदान करने के लिए 'सेवा शुल्क' लेता है।

**भुगतान(Payments):** बैंक अपने ग्राहकों की ओर से समय-समय पर बीमा शुल्क, किराए, करों, बिजली बिलों आदि का भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, जिसके लिए वे कमीशन लेते हैं।



**प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद(Sale And Purchase Of Securities):** ग्राहक कभी-कभी अपनी प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद के लिए बैंकों से संपर्क करते हैं। इन सेवाओं के लिए बैंक कमीशन लेते हैं।

## बैंक्स के प्रकार(Types Of Banks)

### यूनिवर्सल बैंक(Universal Bank)

यूनिवर्सल बैंकिंग के क्या  
फायदे हैं?(What Are The  
Advantages Of Universal  
Banking?)

विविधताओं में वृद्धि और  
लाभप्रदता में वृद्धि।

बेहतर संसाधन उपयोग।

ब्रांड नाम उत्तोलन।

मौजूदा ग्राहक से लाभ(Existing  
Clientele Leverage)।

मूल्य वर्धित सेवाएं।

‘एक स्थान पर संयोजित खरीदारी  
/वन-स्टॉप शॉपिंग’से बहुत अधिक  
लेन देन लागत कि बचती है।

आसान विपणन

लाभ विविधता

- यह वित्तीय बड़ा बाजार है जहां सभी वित्तीय उत्पादों को एक छत के नीचे बेचा जाता है।
- यह बैंकिंग की एक प्रणाली है जहां बैंक वित्तीय सेवाओं जैसे निवेश बैंकिंग, वाणिज्यिक बैंकिंग, विकास बैंकिंग, बीमा और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें व्यापारी बैंकिंग, म्यूचुअल फंड, लेनदारी लेखा क्रय(Factoring), आवास वित्त आदि शामिल हैं।
- विश्व बैंक के अनुसार, यूनिवर्सल बैंक की परिभाषा इस प्रकार है: यूनिवर्सल बैंकिंग, बड़े बैंक शाखाओं का व्यापक संजाल/नेटवर्क संचालित करते हैं, कई अलग-अलग सेवाएं प्रदान करते हैं, निगम (इक्विटी और ऋण सहित) पर कई दावे करते हैं और कंपनियों के निगमित प्रशासन में सीधे भाग लेते हैं जो निधिकरण या बीमा हामीदार के रूप में बैंकों पर निर्भर हैं।
- 1998 की दूसरी नरसिम्ह समिति ने यूनिवर्सल बैंकिंग की अवधारणा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी दी, जो कि संकीर्ण बैंकिंग की तुलना में एक अलग अवधारणा थी। नरसिम्ह समिति ने सुझाव दिया कि विकास वित्तीय संस्थानों (डीएफआई) को अंततः वाणिज्यिक बैंकों या गैर-बैंक वित्त कंपनियों में बदलना चाहिए।
- हालांकि, आरएच खान समिति ने एक अलग अवधारणा के रूप में सिफारिश करने के बाद भारत में सार्वभौमिक बैंकिंग की अवधारणा की। खान वर्किंग ग्रुप ने यह विचार रखा कि Dfi (विकास वित्त संस्थान) को जल्द से जल्द बैंक बनने की अनुमति दी जानी चाहिए।

### विकास बैंक (Development Bank)

- विकास बैंक मूल रूप से एक बहुउद्देश्यीय वित्तीय संस्थान है जिसमें व्यापक विकास दृष्टिकोण है।
- एक विकास बैंक, इस प्रकार, एक वित्तीय संस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो ऋण, हामीदारी, निवेश और गारंटी संचालन, और प्रचार गतिविधियों के रूप में व्यापार इकाइयों को सभी प्रकार की वित्तीय सहायता (मध्यम और दीर्घकालिक) प्रदान करती है। विशेष रूप से आर्थिक विकास, और व्यक्तिगत रूप से औद्योगिक विकास।

## विभिन्न प्रकार के विकास बैंक क्या हैं?(What Are The Different Kinds Of Development Bank?)

भारत में विकास बैंकों को निम्नलिखित चार समूहों में वर्गीकृत किया गया है:



### औद्योगिक विकास बैंक(Industrial Development Banks):

इसमें शामिल हैं, उदाहरण के लिए, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (Ifci), भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (Idbi) और लघु उद्योग विकास बैंक (Sidbi)।



### कृषि विकास बैंक(Agricultural Development Banks):

इसमें शामिल हैं, उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (Nabard)।



### आवास विकास बैंक(Housing Development Banks):

इसमें शामिल हैं, उदाहरण के लिए, नेशनल हाउसिंग बैंक (Nhb)।



### निर्यात-आयात विकास बैंक(Export-Import Development Banks):

इसमें शामिल हैं, उदाहरण के लिए, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया (Exim Bank)।

## लीड बैंक(Lead Bank)

लीड बैंक एक ऐसा बैंक है जो ऋण प्रबंधन की व्यवस्था की देखरेख करता है। लीड बैंक इस सेवा के लिए एक अतिरिक्त शुल्क प्राप्त होता है, जिसमें संघ/सिंडिकेट सदस्यों की भर्ती करना और वित्तपोषण शर्तों पर समझौता वार्ता/बातचीत करना शामिल है। लीड बैंक उस विशेष भौगोलिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक होता है। वे जिला ऋण आवंटन नीति के प्रमुख उद्देश्य के निष्पादन और उपलब्धि में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

लीड बैंक योजना 1969 में शुरू की गई थी, जो सामाजिक उद्देश्यों के कार्यान्वयन के लिए संगठनात्मक ढांचे पर गाइडिल अध्ययन दल की सिफारिशों पर आधारित थी। यह उन्हें आवंटित जिलों का प्रबंधन करने के लिए व्यक्तिगत बैंकों को मुख्य भूमिका प्रदान करता है। संघ के संदर्भ में बैंक के पास आमतौर पर सबसे बड़ा संसाधन संग्रह होता है, जो जनशक्ति के अतिरिक्त संसाधनों और उनके अधीन जिलों की देखरेख करने के लिए अन्य वित्त प्रदान करता है।

### लीड बैंक योजना के उद्देश्य क्या हैं?(What Are The Objectives Of The Lead Bank Scheme?)

- बेरोजगारी और रोजगार के तहत उन्मूलन।
- गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए जीवन स्तर में सहायनीय वृद्धि।
- समाज के गरीब तबके के लोगों की कुछ बुनियादी जरूरतों का प्रावधान।
- मूल विचार लक्षित और केंद्रित बैंकिंग के लिए एक क्षेत्र दृष्टिकोण का होना था।
- एस. नरीमन की अध्यक्षता में बैंकर समिति ने निष्कर्ष निकाला कि जिले हर क्षेत्र तक पहुँचने के लिए इकाईओं की तरह काम करेंगे और प्रत्येक जिले को एक विशेष बैंक को आवंटित किया जा सकता है जो लीड बैंक की भूमिका निभाएगा।

लीड बैंक योजना नीतियों में बदलाव, संचालन में जटिलता, विभिन्न वित्तीय संस्थानों के बीच सहयोग की कमी और वित्तीय समावेशन में बदलाव के कारण पूरी तरह से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं थी। इस योजना को स्पष्ट दिशानिर्देशों के साथ पुनर्जीवित करने के लिए एक मजबूत आवश्यकता महसूस की गई थी। बैंकरों के वाणिज्यिक निर्णयों का सम्मान करने पर भी वे अपने क्षेत्रीय लक्ष्यों को पूरा करते हैं। भारत सरकार ने एलबीएस में सुधार का सुझाव देने के लिए, आरबीआई के उप-राज्यपाल श्रीमती उषाभारत की अध्यक्षता में एक उच्च-शक्ति समिति का गठन किया। इस समिति का कार्य यह सुझाव देना था कि बैंकिंग क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों को देखते हुए, विशेषकर निजीकरण और स्वायत्तता के दौर में एलबीएस को कैसे पुनर्जीवित किया जाए।

### लीड बैंकों पर उषा थोराट समिति की सिफारिशें क्या थीं?(What Were The Recommendation Of Usha Thorat Committee On Lead Banks?)

लीड बैंकों पर उषा थोराट समिति की सिफारिशें निम्नलिखित थीं:

- देश के असिंचित क्षेत्र में वित्तीय समावेशन में तेजी लाने के लिए एलबीएस को जारी रखा जाना चाहिए।
- निजी क्षेत्र के बैंकों को एलबीएस की कार्ययोजनाओं में अधिक से अधिक भूमिका दी जानी चाहिए, विशेषकर उनकी उपस्थिति के क्षेत्रों में।
- 2,000 से ऊपर की आबादी वाले सभी गाँवों में बैंकिंग सेवाओं को उपलब्ध कराना, और छोटे मूल्य खातों के लिए Kyc (अपने ग्राहक को जानो) मानदंडों में छूट प्रदान करना।
- देश के विभिन्न हिस्सों में कार्यरत बैंकों के बीच सार्थक समन्वय लाने के लिए एक प्रभावी साधन बनाने के लिए, लीड बैंक योजना को सुधार और पुनर्जीवित करने की एक मजबूत आवश्यकता है।

## बैंकिंग क्षेत्र में सुधार (Banking Sector Reforms)

### भारत में बैंकिंग क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया क्या थी? (What was the process of banking sector development in India?)

1921

1921 में, सभी प्रेसीडेंसी बैंकों को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाने के लिए समामेलित किया गया था जो कि यूरोपीय शेयरधारकों द्वारा चलाया जाता था।

1935

उसके बाद अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। पहले चरण के समय में बैंकिंग क्षेत्र की वृद्धि बहुत धीमी थी।

1948

1913 और 1948 के बीच भारत में लगभग 1100 छोटे बैंक थे। वाणिज्यिक बैंकों के कामकाज और गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने के लिए, भारत सरकार बैंकिंग कंपनी अधिनियम, 1949 के साथ आई, जिसे बाद में 1965 के संशोधन अधिनियम (1965 के अधिनियम संख्या 23) के अनुसार बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में बदल दिया गया।

भारतीय रिजर्व बैंक को केंद्रीय बैंकिंग प्राधिकरण के रूप में भारत में बैंकिंग की निगरानी के लिए व्यापक शक्तियों के साथ निहित किया गया था।

1955

आजादी के बाद, 1955 में, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था (भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम - 1955 के तहत) और इसे भारतीय स्टेट बैंक का नाम दिया गया था, आर.बी.आई. को प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए और सभी पर बैंकिंग लेनदेन को संभालने के लिए देश में लाया गया।

1960

भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनी बनाने वाले सात बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1960 में किया गया था।

1969

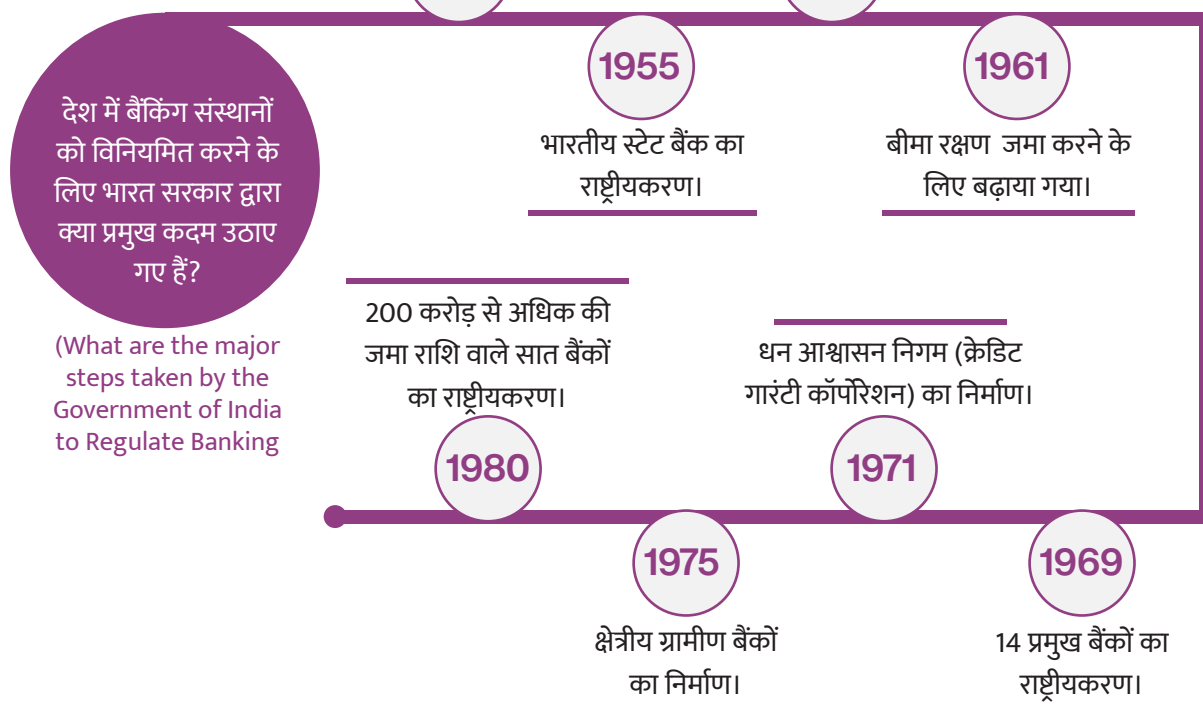
19 जुलाई, 1969 को राष्ट्रीयकरण की बड़ी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। उसी समय देश के 14 प्रमुख भारतीय वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1980 में, एक और छह बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और इस तरह राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 20 हो गई।

1980

200 से अधिक जमाओं के साथ सात और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। वर्ष 1980 तक भारत में लगभग 80% बैंकिंग खंड सरकारी स्वामित्व के अधीन था।

1993

नरसिम्हम समिति के सुझावों पर, 1993 में बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन किया गया और इस प्रकार नए निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए द्वार खोले गए।



### बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पीछे मकसद क्या था?(What was the motive behind nationalisation of banks?)

- यह देखा गया कि अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों जैसे कि कृषि, लघु उद्योग और समाज के कमजोर वर्गों को देश की बैंकिंग प्रणाली द्वारा अपेक्षाकृत अनदेखा किया गया था। उदाहरण के लिए, मार्च 1967 तक कृषि क्षेत्र को कुल ऋण का केवल 2.1% प्राप्त हुआ जबकि उद्योग को 64% आवंटित किया गया।
- यद्यपि यह भारत सरकार द्वारा किया गया था कि वह एकाधिकारवादी प्रवृत्तियों, आर्थिक शक्ति की एकाग्रता और आर्थिक संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से बैंकों पर कुछ नियंत्रण लगाए।
- समय-समय पर ऋण के उपलब्ध संसाधनों का आकलन करने और कई क्षेत्रों में इसके न्यायसंगत और उद्देश्यपूर्ण वितरण को सुनिश्चित करने के लिए 22 दिसंबर, 1967 को राष्ट्रीय धन नियंत्रण परिषद् (नेशनल क्रेडिट कंट्रोल काउंसिल) की स्थापना की गई थी।
- इस तरह के तंत्र ने काम नहीं किया और अंततः राष्ट्रीयकरण को 1969 में एक अध्यादेश के प्रचार के माध्यम से लाया गया, जिसने देश के 14 अग्रणी वाणिज्यिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया। उनमें से कुछ पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय प्रवासी बैंक (IOB), देना बैंक, सिंडिकेट बैंक आदि थे। 1980 में छह और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था।

### **बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पीछे क्या उद्देश्य थे?(What were the objectives behind nationalisation of banks?)**

- लोगों की बचत को अधिकतम संभव तक पहुंचाना और उत्पादक उद्देश्य के लिए उनका उपयोग करना;
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंकिंग परिचालन एक बड़े सामाजिक उद्देश्य द्वारा निर्देशित है और सार्वजनिक नियमों को बंद करने के अधीन है;
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि निजी क्षेत्र के उद्योग और व्यापार की वैध धन की जरूरतें, बड़ी और छोटी, पूरी की जा सकें;
- उत्पादक क्षेत्र और विशेष रूप से कृषि, लघु उद्योग, स्व-नियोजित पेशेवरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए;
- उद्यमियों के नए और प्रगतिशील वर्ग के विकास को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने और देश के विभिन्न हिस्सों में उपेक्षित और पिछड़े क्षेत्रों के लिए नए अवसर पैदा करने के लिए;
- सट्टा के लिए और अन्य अनुत्पादक उद्देश्यों के लिए बैंक ऋण के उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए।

### **निरंतर सुधार की आवश्यकता क्यों थी?(Why was there a need of continuous reform?)**

- 1991 के बाद से लगातार नई आर्थिक नीति के एक भाग के रूप में सुधार किए जाने वाले क्षेत्रों में से एक बैंकिंग क्षेत्र है।
- 1991 तक वाणिज्यिक बैंक और उनकी कमजोरियाँ : बैंक के प्रदर्शन को बिगड़ने में जिन प्रमुख कारकों का योगदान था, वे थे उच्च एसएलआर और सीआरआर, फंड लॉकिंग, सरकारी बॉन्ड पर कम ब्याज दर, लोकलुभावन कारणों से निर्देशित और रियायती ऋण।
- प्रशासित ब्याज दरें।
- प्रतिस्पर्धा का अभाव।

### **सुधार किन समस्याओं को हल करने के लिए किये गए थे?(What problems did the reforms aim at solving?)**

- 2006 में एसएलआर और सीआरआर पर फर्श और टोपी को हटा दिया गया।
- ब्याज दरों को बैंकों को बाजार की स्थितियों के लिए गतिशील रूप से प्रतिक्रिया देने के लिए निर्धारित किया गया था। यहां तक कि अनुसूचित बैंकों की दरों को 2011 में समाप्त कर दिया गया था।
- सार्वजनिक, निजी और विदेशी बैंकों के लिए प्रवेश के समय से एक समान स्तर प्रदान करवाना।
- विवेकपूर्ण मानदंडों को अपनाना - भारतीय रिजर्व बैंक ने आय की मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और बैंकों को सुरक्षित बनाने के प्रावधान के लिए दिशानिर्देश जारी किए
- सुरक्षित बैंकिंग के लिए बेसल नॉर्म्स को अपनाया गया
- बेहतर कार्य संस्कृति और उत्पादकता के लिए वीआरएस
- निजी बैंकों में 74% तक की एफडीआई की अनुमति है।

**बैंकिंग क्षेत्र में सुधार  
के उद्देश्य क्या  
हैं?** (What are the  
objectives of banking  
sector reforms?)



**1**

उन्हें प्रतिस्पर्धी और लाभदायक बनाना।



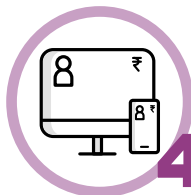
**2**

वैश्विक चुनौतियों का सामना करने  
के लिए क्षेत्र को मजबूत करना।



**3**

बैंकिंग को बुलंद और सुरक्षित बनाने के लिए।



**4**

ग्राहक लाभ के लिए उन्हें तकनीकी रूप  
से आधुनिक बनाने में मदद करना।

**5**

एफडीआई मानदंडों में ढील  
देकर वैश्विक विशेषज्ञता  
और पूंजी उपलब्ध कराना।

## नरसिम्हम समिति (Narasimham Committee)

भारत में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार नरसिम्हम समिति की रिपोर्ट I और II (1991 और 1998 क्रमशः) के आधार पर किए गए थे। इस समिति को भुगतान संतुलन संकट की पृष्ठभूमि के खिलाफ नियुक्त किया गया था। यह वित्तीय प्रणाली से संबंधित सभी कारकों का विश्लेषण करने और इसकी दक्षता और उत्पादकता में सुधार के लिए सिफारिशें देने के लिए स्थापित किया गया था। इस समिति ने अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ भारतीय बैंकिंग मानकों को संरेखित करने के लिए संरचनात्मक उपायों और प्रकटीकरण के मानकों में सुधार और पारदर्शिता के स्तरों पर अधिक जोर दिया।

**1991 में नरसिंहम समिति ने क्या सिफारिशें की थीं?  
(What were the recommendations by  
Narasimham Committee in 1991?)**

- सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र के बैंकों के बीच एक स्तरीय खेल मैदान बनाना।
- वैश्विक परिचालन के लिए एसबीआई जैसे कुछ बैंकों का चयन।
- वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) को कम करना क्योंकि इससे बैंकों के पास ऋण देने के लिए अधिक संसाधन बच जाएंगे।
- बैंकों के उधार देने योग्य संसाधनों को बढ़ाने के लिए नकद आरक्षित अनुपात (CRR) को कम करना।
- तर्कसंगत और बेहतर लक्ष्यीकरण प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण देना क्योंकि इसका बड़ा हिस्सा व्यर्थ है और इसका अधिकांश हिस्सा गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में बदल रहा है।
- बेहतर जोखिम प्रबंधन और संचालन में पारदर्शिता के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों का परिचय।
- ब्याज दरों को दरकिनार करना।
- संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) स्थापित करें जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कुछ खराब ऋणों को ले सकती है और उन्हें कमीशन के लिए इकट्ठा कर सकती है।

**1998 में समिति ने क्या सिफारिशें की थीं?  
(What were the recommendations  
by the committee in 1998?)**

- 1998 में फिर से, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने 1992 से बैंकिंग सुधारों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने और भारत के वित्तीय संस्थानों को और मजबूत करने के लिए श्री एम नरसिंहम की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की।
- कुछ बैंकों को विलय करके मजबूत बैंकिंग प्रणाली की आवश्यकता है, जिनका उद्योग पर कई गुना प्रभाव पड़ेगा।
- एनपीए के लिए सख्त मानदंड और संकीर्ण बैंकिंग की अवधारणा जो बैंकों को केवल अल्पकालिक और जोखिम मुक्त परिसंपत्तियों में अपने फंड को रखने की अनुमति देती है।
- PSB के लिए अधिक से अधिक स्वायत्तता, ताकि वे अपने अंतरराष्ट्रीय समकक्षों के अनुसार कार्य कर सकें।
- बढ़ी हुई स्वायत्तता के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों में भारत सरकार की इक्विटी घटकर 33% रह जाती है।
- निगमित रणनीति तैयार करने और सरकारी इक्विटी में कमी के माध्यम से शेयरधारक मूल्य को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार बनाने के लिए बैंकों के बोर्ड के कार्यों की समीक्षा करना।
- बैंकों की जोखिम अवशोषण क्षमता में सुधार करने के लिए पूँजी पर्याप्तता मानदंड बढ़ाना।
- समिति ने 2000 तक पूँजी पर्याप्तता अनुपात को 9% और 2002 तक 10% बढ़ाने का लक्ष्य रखा। समिति ने उन बैंकों के लिए दंडात्मक प्रावधानों की सिफारिश की जो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहते हैं।

**समिति द्वारा सिफारिशों को लागू करना(Implementation of the  
recommendations by the committee)**

- इन (नरसिंहम समिति II) सिफारिशों को लागू करने के लिए, 1998 में आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र सुधारों के दूसरे चरण की शुरुआत की, जिसमें पूँजी पर्याप्तता अनुपात 1% बढ़ा और चरणबद्ध तरीके से संपत्ति के वर्गीकरण और प्रावधान के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों को कड़ा किया गया।
- इसने मार्च 2001 तक पूँजी पर्याप्तता अनुपात को 9% तक लाने का लक्ष्य रखा।
- अक्टूबर 1999 में मार्च 1999 तक स्वायत्त स्थिति के मानदंड की पहचान की गई और 17 बैंकों को स्वायत्तता के लिए योग्य माना गया।



- वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज अधिनियम 2002 (SARAFESI अधिनियम 2002) को एनपीए की समस्याओं पर अंकुश लगाने के लिए शुरू किया गया था।
- 2008 के आर्थिक संकट के दौरान, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र का प्रदर्शन उनके अंतर्राष्ट्रीय समकक्षों की तुलना में कहीं बेहतर था।
- इसे नरसिम्हम समिति- II की सिफारिशों के सफल कार्यान्वयन का श्रेय दिया गया था, जिसमें पूंजी पर्याप्तता मानदंडों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूँजीकरण का विशेष संदर्भ था।
- दोनों समितियों का प्रभाव इतना महत्वपूर्ण रहा है कि वित्तीय-आर्थिक क्षेत्र के पेशेवरों ने वहां सकारात्मक योगदान की सराहना की है।

## नई बैंक की लाइसेंस मानदंड (New Bank Licence Criteria )

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई ) ने ऐसे देश में नए बैंक स्थापित करने के लिए दो प्रारंभिक लाइसेंस दिए हैं, जहाँ दो में से केवल एक घर में औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच है।

IDFC Ltd (IDFC.NS) और बंधन वित्तीय सेवाएं के लिए लाइसेंस की मंजूरी, सुस्त राज्य उधारदाताओं के प्रभुत्व वाले क्षेत्र के लिए एक सतर्क प्रयोग की शुरुआत करती है, जिनमें से कई ग्रामीण क्षेत्रों या कस्बों में विस्तार करने के लिए अनिच्छुक हैं या बैंकिंग पैठ कम है। 2004 में यस बैंक (YESB.NS) के बाद से कोई नया भारतीय बैंक नहीं बनाया गया है।

**नए बैंक लाइसेंस जारी करने के लिए आरबीआई द्वारा दिशानिर्देशों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? (What are the key features of the guidelines by RBI for issuing new bank license?)**

**योग्य प्रवर्तक (Eligible Promoters):** निजी क्षेत्र में इकाइयाँ / समूह, सार्वजनिक क्षेत्र में संस्थाएँ और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFC) पूर्ण स्वामित्व वाली गैर-सहकारी वित्तीय होल्डिंग कंपनी (NOFHC) के माध्यम से एक बैंक स्थापित करने के लिए पात्र होंगी।

**‘फिट और उचित’ मानदंड (‘Fit and Proper’ criteria):** संस्थाओं / समूहों के पास सही प्रत्यय/परिचय पत्र और अखंडता का पिछला रिकॉर्ड होना चाहिए, 10 साल के सफल पूर्व निष्पादन अभिलेख के साथ आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए, आरबीआई अन्य नियामकों और प्रवर्तन और जांच संस्था से प्रतिक्रिया मांग सकता है।

**NOFHC की व्यावसायिक संरचना(Corporate structure of the NOFHC):** NOFHC प्रवर्तक के पूर्ण स्वामित्व वाली होगी।

**प्रचारक समूह।** NOFHC बैंक के साथ-साथ समूह की अन्य सभी वित्तीय सेवा संस्थाओं को भी रखेगा।

**बैंकों के लिए न्यूनतम मतदान इक्विटी पूंजी की आवश्यकता और NOFHC द्वारा शेयरधारिता (Minimum voting equity capital requirements for banks and shareholding by NOFHC):** किसी बैंक के लिए शुरुआती न्यूनतम चुकता इक्विटी पूंजी मतदान 5 बिलियन होगी। NOFHC शुरू में बैंक के भुगतान किए गए प्रदत्त मतदान इक्विटी पूंजी(paid-up voting equity capital) का न्यूनतम 40 प्रतिशत रखेगा, जिसे पांच साल की अवधि के लिए बंद कर दिया जाएगा और जिसे 12 वर्षों के भीतर 15 प्रतिशत तक लाया जाएगा। बैंक द्वारा व्यापार शुरू करने के तीन साल के भीतर बैंक अपने शेयर, शेयर बाजारों में सूचीबद्ध करवाएगा।

**विनियामक ढांचा (Regulatory framework):** बैंक संबंधित अधिनियमों, प्रासंगिक विधियों और निर्देशों, विवेकपूर्ण नियमों और आरबीआई और अन्य नियामकों द्वारा जारी किए गए अन्य दिशानिर्देशों / निर्देशों के प्रावधानों द्वारा शासित होगा। NOFHC को आरबीआई के साथ एक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (NBFC) के रूप में पंजीकृत किया जाएगा और आरबीआई द्वारा जारी किए गए निर्देशों के एक अलग समूह द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

**बैंक में विदेशी शेयरहोल्डिंग (Foreign shareholding in the bank):** नए बैंक में कुल गैर-निवासी शेयरधारिता पहले 5 वर्षों के लिए 49% से अधिक नहीं होगी, जिसके बाद यह मौजूदा नीति के अनुसार होगा।

**निगम शासन प्रणाली - NOFHC (Corporate governance of NOFHC):** NOFHC के निदेशकों में कम से कम 50% स्वतंत्र निदेशक होना चाहिए। निगम संरचना को RBI द्वारा समेकित आधार पर बैंक और NOFHC के प्रभावी पर्यवेक्षण को बाधित नहीं करना चाहिए।

**NOFHC के लिए विवेकपूर्ण मानदंड (Prudential norms for the NOFHC):** विवेकपूर्ण मानदंडों को NOFHC पर स्वतंत्र आधार (Stand alone basis) के साथ-साथ समेकित आधार पर लागू किया जाएगा और मानदंड बैंक की तरह ही इसी तर्ज पर होंगे।

**अनावरण मानदंड(Exposure norms):** एनओएफएचसी और बैंक का प्रमोटर समूह से किसी प्रकार का भी अनावरण नहीं होगा। बैंक NOFHC द्वारा आयोजित किसी भी वित्तीय संस्थाओं के इक्विटी / ऋण पूंजी साधन(debt capital instruments) में निवेश नहीं करेगा।

**बैंक के लिए व्यवसाय योजना(Business Plan for the bank):** व्यवसाय योजना यथार्थवादी और व्यवहार्य होनी चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि बैंक वित्तीय समावेशन को कैसे प्राप्त करना चाहता है।

### बैंक के लिए अन्य शर्तें: (Other conditions for the bank: )

- बैंक की समिति / बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों का बहुमत होना चाहिए।
- बैंक बिना बैंक वाले ग्रामीण केंद्रों में कम से कम 25 प्रतिशत शाखाएं खोलेगा (नवीनतम जनगणना के अनुसार 9,999 तक की आबादी)।
- बैंक मौजूदा घरेलू बैंकों के लिए प्राथमिकता वाले ऋण लक्ष्य और उप-लक्ष्य का पालन करेगा।
- गैर-वित्तीय कारोबार से 40 प्रतिशत या अधिक संपत्ति / आय वाले समूहों द्वारा पदोन्नत बैंकों को 5 बिलियन के प्रत्येक खंड के लिए भुगतान किए गए मतदान इक्विटी पूंजी को 10 बिलियन से आगे बढ़ाने के लिए RBI की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी।
- किसी भी नियम और शर्तों का अनुपालन बैंक के लाइसेंस को रद्द करने सहित दंडात्मक उपायों को आकर्षित करेगा।

**बैंक में एनबीएफसी को बढ़ावा देने / परिवर्तित करने के लिए अतिरिक्त शर्तें:** मौजूदा एनबीएफसी को, यदि योग्य माना जाता है, तो एक नए बैंक को बढ़ावा देने या खुद को बैंकों में बदलने की अनुमति दी जा सकती है।

## हाल के अन्य समितियां (Other Recent Committees)

### नचिकेत मोर समिति (Nachiket Mor Committee)

छोटे व्यवसायों और कम आय वाले परिवारों के लिए व्यापक वित्तीय सेवाओं की समिति आरबीआई द्वारा नचिकेत मोर की अध्यक्षता में स्थापित की गई थी। अपनी अंतिम रिपोर्ट में, समिति ने भारत में पूर्ण वित्तीय समावेशन और वित्तीय गहनता के लिए छह दृष्टि बयानों को रेखांकित किया है।

**समिति द्वारा उल्लिखित छः दृष्टि कथन क्या हैं? (What are the six vision statements outlined by the committee?)**

1

**सार्वभौमिक इलेक्ट्रॉनिक बैंक खाता (Universal Electronic Bank Account (UEBA)):**

प्रत्येक भारतीय निवासी, अठारह वर्ष से अधिक आयु का, व्यक्तिगत, पूर्ण-सेवा, सुरक्षित और सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक बैंक खाता होगा।

2

**उचित शुल्क पर भुगतान सेवाओं और जमा उत्पादों के लिए सर्वव्यापी पहुंच:**

समिति का मानना है कि भारत में प्रत्येक निवासी भुगतान पहुंच बिंदु से पंद्रह मिनट की पैदल दूरी के भीतर होगा।

**3****सस्ती औपचारिक जमा धन के लिए पर्याप्त पहुंच:**

प्रत्येक कम आय वाले घर और छोटे-व्यवसाय को औपचारिक रूप से विनियमित ऋणदाता तक पहुंच होगी जो उनकी धन की जरूरतों का आकलन करने और उन्हें पूरा करने में सक्षम है। इस तरह के ऋणदाता को किफायती मूल्य पर उपयुक्त ऋण उत्पादों की पूरी श्रृंखला की पेशकश करने में सक्षम होना चाहिए।

**4****उचित शुल्क पर जमा और निवेश उत्पादों की एक सीमा तक सार्वभौमिक पहुंच:**

प्रत्येक कम आय वाले घर और छोटे-व्यवसाय में प्रदाताओं तक पहुंच होगी जो उन्हें उपयुक्त निवेश और जमा उत्पादों की पेशकश कर सकते हैं। ऐसी सेवाएं उन्हें उचित शुल्क पर उपलब्ध होनी चाहिए।

**5****उचित शुल्क पर बीमा और जोखिम प्रबंधन उत्पादों की एक सीमा तक सार्वभौमिक पहुंच:**

प्रत्येक कम आय वाले घरेलू और छोटे व्यवसाय में उन प्रदाताओं तक पहुंच होगी जो उन्हें उपयुक्त बीमा और जोखिम प्रबंधन उत्पादों की पेशकश करने की क्षमता रखते हैं।

इन उत्पादों को कम से कम उन्हें संबंधित जोखिमों का प्रबंधन करने की अनुमति देनी चाहिए:

- (a) वस्तुओं के मूल्य में उतार चढ़ाव
- (b) मानव की दीर्घायु, विकलांगता और मृत्यु;
- (c) पशुधन की मृत्यु;
- (d) वर्षा; और
- (e) संपत्ति को नुकसान।

**6****उपयुक्तता का अधिकार:**

प्रत्येक कम आय वाले घर और छोटे व्यवसाय के लिए कानूनी रूप से संरक्षित अधिकार होगा जो केवल उपयुक्त वित्तीय सेवाओं की पेशकश करेगा। यदि उसे लगता है कि उपयुक्तता स्थापित करने की उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था या उसमें घोर लापरवाही थी, तो उसे कानूनी निवारण प्राप्त करने का अधिकार होगा।

**इस समिति द्वारा दी गई प्रमुख सिफारिशें क्या हैं?(What are the key recommendations given by this committee?)**

- 1 जनवरी, 2016 तक 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीयों को एक सार्वभौमिक बैंक खाता प्रदान करना। इसे प्राप्त करने के लिए, जमा और भुगतान के लिए भुगतान बैंकों और क्रेडिट आउटरीच के लिए थोक बैंकों के साथ एक लंबवत विभेदित बैंकिंग प्रणाली। इन बैंकों को पूंजी के माध्यम से 50 करोड़ रुपये की आवश्यकता है, जो कि नए बैंकों के लिए लागू होने वाले दसवें हिस्से का लाइसेंस है।
- आधार बैंक खातों की संख्या में तेजी से विस्तार की दिशा में प्रमुख चालक होगा।
- सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में जमा और अग्रिम जैसे जिला स्तर पर निगरानी।
- ऋण देने में कठिनाई के आधार पर क्षेत्रों और क्षेत्रों के समायोजन के साथ 50 प्रतिशत प्राथमिकता वाले क्षेत्र ऋण लक्ष्य को समायोजित किया।

## बी. पी. जे. नायक समिति (B. P. J. Nayak Committee)

- पीएसयू बैंकों में कॉनिगम संचालन के बारे में सिफारिशें करने के लिए आरबीआई द्वारा इसका गठन किया गया था।

### नायक समिति ने क्या सिफारिशें दी थीं?(What were the recommendations given by the Nayak committee?)

- बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम, एसबीआई अधिनियम और एसबीआई (सब्सिडियरी बैंक) अधिनियम का परिमार्जन और निष्कासन।
- कंपनी अधिनियम के अनुसार कंपनियों में पीएसबी का रूपांतरण।
- कंपनी अधिनियम के तहत एक बैंक निवेश कंपनी / बीआईसी (Bank Investment Company) का गठन; PSB में केंद्र सरकार द्वारा शेयरों का बीआईसी में स्थानांतरण।
- बदले में बीआईसी (Bank Investment Company), पीएसबी (Public Sector Banks) के समिति / बोर्डों को नियंत्रित करने वाली शक्ति सौंप देगा।
- सरकार केवल निवेश पर कमाई पर नियंत्रण करेगी।
- केंद्र सरकार के लिए निवेश पर उचित वापसी बीआईसी की जिम्मेदारी होगी।
- पीएसबी के निदेशकों और शीर्ष कार्यकारी अधिकारियों के अंदर सीईओ की नियुक्ति बैंक बोर्ड्स ब्यूरो की जिम्मेदारी होगी, जिसमें तीन सेवारत या सेवानिवृत्त बैंक अध्यक्ष शामिल होंगे और सरकार किसी भी तरह से इस निर्णय में शामिल नहीं होगी।
- नायक समिति भी सभी शेयरधारकों को आनुपातिक मतदान के अधिकार और सरकारी हिस्सेदारी को 40% तक कम करने की सिफारिश करती है।

## बासेल मानदंड: विवेकपूर्ण मानदंडों और पूंजी पर्याप्तता (Basel Norms: Prudential Norms And Capital Adequacy)

- नरसिम्हम समिति की सिफारिशों को लागू करते हुए, आरबीआई ने निर्धारित किया कि बैंकों को विवेकपूर्ण मानदंडों के रूप में, 2 वर्ष की अवधि में सभी हानि परिसंपत्तियों या गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के लिए 100 प्रतिशत प्रावधान करना चाहिए।
- पूंजी पर्याप्तता मानदंड बैंकों को 8 प्रतिशत की परिसंपत्ति भारित जोखिम अनुपात के लिए पूंजी प्राप्त करने की आवश्यकता थी। एक बैंक की वास्तविक पूंजी का आकलन उसकी परिसंपत्तियों की जोखिम को ध्यान में रखने के बाद किया जाता है। इनसॉल्वेंसी के खिलाफ गारंटी देने के लिए परिसंपत्ति की जोखिम के लिए एक तकिया प्रदान करना आवश्यक है।



- 1974 में जर्मन बैंक हेस्टैट(German Bank Herstatt) की विफलता के बाद, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (Bank of International Settlements(BIS)) बेसल, स्विट्जरलैंड के तत्वावधान में बेसेल समिति द्वारा बैंकिंग पर्यवेक्षण पर पूंजी पर्याप्तता अनुपात के लिए अंतरराष्ट्रीय मानदंड निर्धारित किया गया था।
- यह बैंक पर्यवेक्षकों की एक समिति है जिसमें G10 देशों के प्रत्येक सदस्य शामिल हैं। समिति विशिष्ट पर्यवेक्षी समस्याओं से निपटने की चर्चा के लिए एक मंच है।
- यह सिफारिशों के पहले समूह के साथ आया था जिसे बेसल I कहा जाता है। इनमें बैंक की कुल जोखिम वाली परिसंपत्तियों के 8 प्रतिशत की न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता शामिल थी।
- कई भारतीय बैंकों को पूंजी पर्याप्तता मानदंडों को पूरा करने के लिए सार्वजनिक मुद्दों के लिए जाना पड़ा। बाद में यह महसूस किया गया कि बेसल I मानदंडों ने केवल वित्तीय जोखिम को संबोधित किया।
- तदनुसार, बेसल II नामक मानदंडों का एक संशोधित समूह जून 2004 में लाया गया था। ये अधिक जटिल मानदंड हैं और पूंजी आवश्यकता, पर्यवेक्षी समीक्षा और बाजार अनुशासन के तीन स्तंभों पर आधारित हैं।
- बेसल II मानदंडों के बावजूद, 2008 के वित्तीय बाजार संकट ने और अधिक कठोरता की आवश्यकता का खुलासा किया।
- बेसल III को वित्तीय और आर्थिक तनाव से उत्पन्न होने वाले झटकों को अवशोषित करने की बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता में सुधार करने के लिए दिसंबर 2010 में प्रस्तावित किया गया था।
- आरबीआई ने 31 मार्च, 2018 तक चरणबद्ध तरीके से जनवरी 2013 से बेसल III मानदंडों को अपनाने के निर्देश जारी किए हैं।
- इसके लिए पूंजी के नए जलसेक की आवश्यकता होगी जिसके लिए सरकारी नियंत्रण को कमजोर किए बिना PSU बैंक पूंजी को कमजोर करने का निर्णय लिया गया है।

## धन(Money)

पैसा हमारे जीवन के दैनिक जीवन में एक बहुत ही आवश्यक भूमिका निभाता है। धन एक ऐसी चीज है जो आम तौर पर विनिमय के साधन के रूप में स्वीकार्य है और जो एक ही समय में मूल्य के माप और भंडार के रूप में कार्य करता है। यह कुछ ऐसा भी है जिसे व्यापक रूप से विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है जिसकी गारंटी देश की सरकार देती है।

## धन के कार्य क्या हैं?(What Are The Functions Of Money?)

पैसा चार कार्यों का विषय है: एक माध्यम, एक माप, एक मानक और एक भंडार | पहले दो को धन के प्राथमिक कार्य कहा जाता है, जबकि अन्य दो को द्वितीयक कार्य या व्युत्पन्न कार्य कहा जाता है क्योंकि यह प्राथमिक कार्य से लिया गया है।

| प्राथमिक कार्य(Primary Functions)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | माध्यमिक कार्य(Secondary Functions)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>विनिमय का माध्यम(Medium Of Exchange):</b><br/>चूंकि धन की सामान्य स्वीकार्यता है, यह विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करता है। यह हमारे दैनिक लेन देन की सुविधा प्रदान करता है। पैसे के भुगतान पर, विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की जा सकती है।</p> <p><b>मूल्य का माप(Measure Of Value):</b><br/>धन का उपयोग अर्थव्यवस्था में इकाइयों को मापने के लिए किया जाता है। हम पैसे के मामले में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मापते हैं, जैसे कि हम मीटर के संदर्भ में किलो या दूरी के आधार पर वजन मापते हैं। यह विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के बीच विनिमय की दरों को निर्धारित करने में हमारी मदद करता है।</p> | <p><b>मूल्य का भंडार(Store Of Value):</b><br/>धन मूल्य के भंडार के रूप में कार्य करता है। चूंकि यह कोई समाप्ति की तारीख नहीं है, और यह मूल्य में तुलनात्मक रूप से स्थिर है, अन्य परिसंपत्तियों के मूल्य को धन के रूप में संग्रहीत किया जा सकता है। इसके अलावा, समय के साथ क्रय शक्ति के भंडार के रूप में धन कार्य करता है। धन का यह कार्य उपयोगी है, क्योंकि हम में से अधिकांश इसे प्राप्त करने पर अपनी आय तुरंत खर्च नहीं करना चाहते हैं, बल्कि तब तक इंतजार करना पसंद करते हैं जब तक कि हमारे पास समय या खरीदारी करने की इच्छा न हो।</p> <p><b>मानक या आस्थगित भुगतान(Standard Or Deferred Payment):</b><br/>धन केवल माल और सेवाओं के वर्तमान लेनदेन को ही नहीं बल्कि उनके क्रेडिट लेनदेन को भी सुगम बनाता है। यह तब लेन-देन की सुविधा प्रदान करता है जब वर्तमान वस्तुओं का भविष्य के भुगतान के खिलाफ आदान-प्रदान किया जाता है। आधुनिक दुनिया में, आस्थगित भुगतान के थोक केवल पैसे के संदर्भ में निर्धारित होते हैं।</p> <p><b>मूल्य का हस्तांतरण(Transfer Of Value):</b><br/>इसमें किसी भी संपत्ति के मूल्य को किसी अन्य या किसी संस्था या किसी भी स्थान पर धन हस्तांतरित करना शामिल है। यह स्थानांतरण स्थानों, समय और परिस्थितियों के बावजूद हो सकता है। क्रय शक्ति का हस्तांतरण, जो वाणिज्य और अन्य लेन-देन में आवश्यक है, धन के कारण उपलब्ध हो गया है।</p> |

## पैसे का वर्गीकरण(Classification Of Money )

### वास्तविक धन(Actual Money)

धन जो वास्तव में अर्थव्यवस्था में परिचालित होता है जिसके लिए सभी भुगतान किए जाते हैं और सामान्य क्रय शक्ति को विनिमय के माध्यम के रूप में रखा जाता है। पाकिस्तान में, सभी मूल्यवर्ग के नोट और सिक्के वास्तविक पैसे हैं।

### खाते का पैसा(Money of Account)

खाते का पैसा - जिसके संदर्भ में कीमतें व्यक्त की जाती हैं और खातों को बनाए रखा जाता है। आम तौर पर, वास्तविक धन और खाते का पैसा समान होता है लेकिन कभी-कभी वे अलग होते हैं। उदाहरण के लिए: पैसा पाकिस्तान में खाते का पैसा है लेकिन यह वास्तविक पैसा नहीं है। अब के दिन यह प्रचलन में नहीं है।

### धातु धन(Metallic Money)

यह सोने और चांदी जैसी धातु से बना है। अर्थव्यवस्था में घूमने वाले सभी मूल्यवर्ग के सिक्के धात्विक धन के उदाहरण हैं।

### कागजी मुद्रा(Paper Money)

कागज से बने पैसे को कागजी मुद्रा कहा जाता है। इसमें विभिन्न मूल्यवर्ग शामिल हैं।

### कानूनी निविदा धन(Legal Tender Money)

वह धन जिसके पीछे कानूनी स्वीकृति है और लोग सभी भुगतानों में इसे स्वीकार करने के लिए कानून द्वारा बाध्य हैं। कोई भी इसे मानने से इंकार नहीं कर सकता।

### वैकल्पिक धन (Optional Money)

मुद्रा का वह रूप जो विनिमय के माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है, लेकिन इसके पीछे कोई कानूनी शक्ति नहीं होती है। इसमें क्रेडिट उपकरण जैसे चेक, बिल या विनिमय और सीडीआर आदि शामिल हैं जो आमतौर पर भुगतान में स्वीकार्य होते हैं।



### चलायमान मुद्रा(Hot Money)

धन जो वित्तीय बाजारों के बीच नियमित रूप से और जल्दी से आगे बढ़ता है ताकि निवेशक यह सुनिश्चित कर सकें कि उन्हें सबसे अधिक अल्पकालिक ब्याज दर उपलब्ध हो। चलायमान मुद्रा लगातार उन देशों से कम ब्याज दरों वाले देशों में जाती है, जो विनिमय दर (यदि उच्च राशि है) को प्रभावित करने वाले उच्च ब्याज दर वाले हैं और देश के भुगतान संतुलन को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं।

### वस्तु मुद्रा(Commodity Money)

इसका मूल्य उस वस्तु से लिया जाता है जिसमें से इसे बनाया जाता है। वस्तु खुद पैसे का प्रतिनिधित्व करती है, और पैसा एक वस्तु है। उदाहरण के लिए, जिन वस्तुओं को विनिमय के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया गया है, उनमें सोना, चांदी, तांबा, नमक, पेपरकॉर्न, चावल, बड़े आकार आदि शामिल हैं।

### वाणिज्यिक बैंक मनी(Commercial Bank Money)

ये मांग जमा(demand deposit) हैं, जिनका दावा वित्तीय संस्थानों के खिलाफ किया जाता है, जिनका उपयोग सामान और सेवाओं की खरीद के लिए किया जा सकता है।

**धातु के पैसे को वर्गीकृत करने के दो तरीके क्या हैं?(What are the two ways in which metallic money can be classified?)**

### पूर्ण रूपेण धन(Full bodied money):

यदि धन का अंकित मूल्य एक वस्तु के रूप में इसके मूल्य के बराबर है, तो इसे पूर्ण रूपेण धन कहा जाता है। यदि अंकित मूल्य के एक सोने के सिक्के का मूल्य 100 / - रु। है, जिसमें 100 / - रु। का सोना शामिल है, तो इसे पूर्ण धनराशि या कभी-कभी मानक धन कहा जाएगा।

### टोकन मनी(Token Money):

यदि मुद्रा का अंकित मूल्य वस्तु या आंतरिक मूल्य से अधिक है, तो इसे टोकन मनी के रूप में जाना जाता है।





**कागजी मुद्रा को वर्गीकृत करने के तरीके क्या हैं?(What are the ways in which paper money can be classified?)**

#### **प्रतिनिधि कागजी धन(Representative Paper Money):**

यदि पूर्ण शारीरिक सिक्कों या सोने की ईंट के सौ प्रतिशत स्वर्ण आरक्षित रखकर कागज जारी किया जाता है, तो इसे प्रतिनिधि धन कहा जाएगा।

#### **परिवर्तनीय कागजी मुद्रा(Convertible Paper Money):**

अगर कागजी मुद्रा को सोने के सिक्कों या सोने के ईंट में बदला जा सकता है, तो इसे परिवर्तनीय कागजी मुद्रा कहा जाता है। इस प्रकार का धन इसके पीछे समान राशि के धातु आरक्षित रखने के द्वारा जारी किया जाता है।

#### **फिएट या अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रा (Fiat or In-convertible Paper Money):**

यह पूर्ण शरीर सिक्के या मांग पर स्वर्ण ईंट में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। यह आमतौर पर इसके पीछे धातु आरक्षित रखने के बिना जारी किया जाता है।

**कानूनी निविदा धन को वर्गीकृत करने के दो तरीके क्या हैं?(What are the two ways in which legal tender money can be classified?)**

#### **सीमित कानूनी निविदा(Limited Legal Tender):**

जो केवल एक निश्चित सीमा तक ही भुगतान में दी जा सकती है। आदाता उसे उस सीमा से परे मानने से इंकार कर सकता है। कई एशियाई देशों में 25 पैसे के सिक्के और कम मूल्य के सिक्के सीमित कानूनी निविदा हैं। इन सिक्कों को केवल 50 रुपये तक के भुगतान के रूप में दिया जा सकता है।

#### **असीमित कानूनी निविदा(Unlimited Legal Tender):**

असीमित वैध मुद्रा का मतलब है कि पैसे जो किसी भी सीमा तक भुगतान में दिया जा सकता है।

### **भारतीय रुपये की स्थिति(Position Of Indian Rupee )**

भारतीय रुपया मानक मुद्रा(standard money) और प्रतीक मुद्रा(token money) का मिश्रण है। मानक मुद्रा की तरह, यह असीमित कानूनी निविदा है, और प्रतीक/टोकन मुद्रा की तरह, इसका अंकित मूल्य आंतरिक मूल्य से अधिक है। भारतीय रुपये को चांदी (अभी वर्तमान में निकेल धातु) पर मुद्रित नोट कहा जाता है।